यूपी निर्यात तैयारी रैंकिंग में चौथे और लैंडलॉक्ड राज्यों में नंबर-1

निर्यात नीति, ODOP और निर्यातकों को दी गई सहूलियतों से रैंकिंग में हुआ सुधार

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लाई गई नीतियों का असर दिखने लगा है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 की रैंकिंग में यूपी चौथे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं, लैंडलॉक्ड राज्यों में प्रथम स्थान हासिल किया है। 2022 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ओवरऑल सातवें स्थान पर और लैंडलॉक्ड राज्यों में दूसरे स्थान पर था। पिछले दो साल में रैंकिंग में आए इस सुधार की सबसे बड़ी वजह राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नीतियां हैं। टॉप तीन में तटीय राज्य शामिल हैं। रैंकिंग में पहले तीन स्थान पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे तटीय राज्य रहे हैं। समुद्री तट न होने के कारण उत्तर प्रदेश के निर्यातकों को बंदरगाहों तक माल पहुंचाने में अधिक समय और लागत वहन करनी पड़ती है।

महाराष्ट्र पहले, तमिलनाडु दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर

निर्यात बढ़ाने में इन नीतियों का रहा अहम योगदान

निर्यात बढ़ाने और निर्यात तैयारी सूचकांक की रैंकिंग में सुधार एक बड़ी वजह राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक जिला-एक उत्पाद योजना है। साथ ही निर्यातकों को दी गई सहूलियतों का असर भी दिखा है। राज्य सरकार निर्यातकों के लिए कई तरह की सब्सिडी भी शुरू की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, लॉजिस्टिक्स सुधार, रोड-कनेक्टिविटी और ड्राई पोर्ट जैसी पहल ने निर्यात को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकार द्वारा माल भाड़ा व्यय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग शुल्क, कुरियर और एयर-फ्रेट व्यय, निर्यात क्रेडिट गारंटी पर प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाओं ने निर्यातकों का लागत बोझ कम किया है, जिससे वैश्विक बाजार में यूपी के उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने हैं। उत्तर प्रदेश का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का निर्यात लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले आठ साल में दोगुना से अधिक हुआ है। यूपी का निर्यात देश के कुल निर्यात का करीब 4.7 प्रतिशत है। यूपी के निर्यात का सबसे अधिक उत्पाद अमेरिका होता है। दूसरे स्थान पर यूएई, तीसरे स्थान पर जर्मनी और चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम में निर्यात होता है। अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश एक तरफ जहां नए देशों में अपना बाजार बढ़ा रहा है। वहीं, राज्य सरकार की तरफ से निर्यातकों को दी जाने वाली रियायतों में भी बढ़ोतरी की गई है।

AI Image

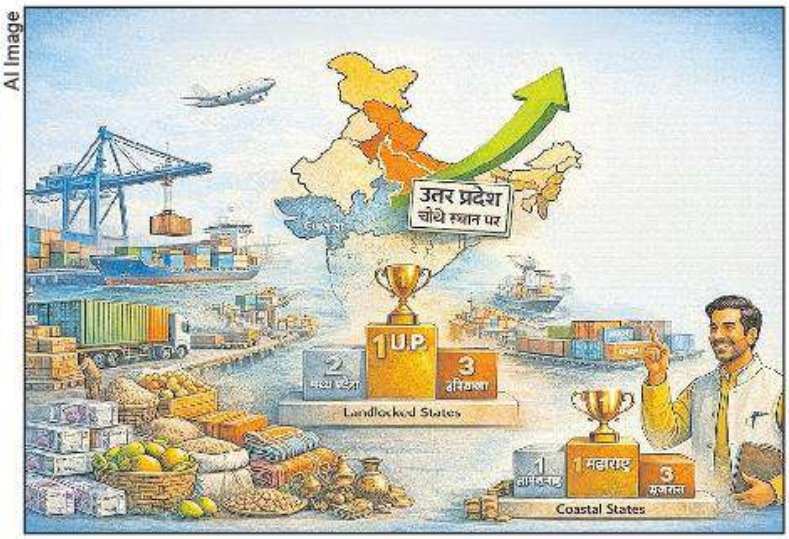

70 संकेतकों पर किया गया मूल्यांकन

नीति आयोग ने EPI-2024 रैंकिंग तैयार करते समय चार प्रमुख स्तंभ-निर्यात अवसंरचना, बिजनेस इको सिस्टम, नीति एवं सुशासन और निर्यात प्रदर्शन के साथ 13 उप-स्तंभों के 70 संकेतकों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन किया।

इंटरनैशनल ट्रेड शो से सीधे मिले निर्यातक

निर्यात बढ़ने के पीछे नीतियों के साथ-साथ इंटरनैशनल ट्रेड शो का भी अहम योगदान रहा। यूपी सरकार पिछले तीन साल से इंटरनैशनल ट्रेड शो का आयोजन कर रही है। इसके माध्यम से यूपी के एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बायर्स से सीधा संपर्क मिला, जिससे नए बाजारों में प्रवेश और निर्यात ऑर्डरों में वृद्धि दर्ज की गई। इससे प्रदेश के हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य-प्रसंस्करण, चमड़ा, फार्मा और एग्री-बेस्ड उत्पादों का निर्यात बढ़ा है।